

समाचार पत्रों की कतरनें

अगस्त, 2026

हिमाचल दस्तक, दिनांक-11 अगस्त 2026

सड़क हादसों के घायलों को मिल रहा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, हमीरपुर में 14 लोग हुए लाभान्वित

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बोलीं उपायुक्त गंधर्वा राठौर

हिमाचल दस्तक। हमीरपुर

उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों, दुर्घटनाओं की रोकथाम, जागरूकता कार्यक्रमों और सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की।

उपायुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए पीएम राहत योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का प्रावधान है। जिला हमीरपुर में भी यह योजना शुरू कर दी गई है और अभी हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल 14 लोगों को इस सविधा



का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई माह के दौरान जिले में 12 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे इस बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे और परिवहन विभाग के अधिकारियों को सभी मुख्य सड़कों, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सड़कों की सही मार्किंग करवाने तथा उपयुक्त स्थानों पर दिशा-सचक और

स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की तत्काल मदद कर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने वाले जिले के दो व्यक्तियों के नाम राहवीर योजना के तहत 'गुड सेमेरिटन' पुरस्कार के लिए अनुशंसित किए गए हैं। बैठक में एसपी बलवीर सिंह, नगर निगम के आयुक्त रakesh शर्मा, एसडीएम संजीत सिंह, आरटीओ राजीव ठकुर आदि मौजूद रहे।

प्रदेश में 15 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के नहीं होंगे चालान

उपमुख्यमंत्री बोले-सरकार 12 से बढ़ाकर 15 साल करना चाहती है अवधि, केंद्र से उठाया मामला

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु 12 से बढ़ाकर 15 साल करने का मामला विधानसभा में उठा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने



कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी 15 साल तक के वाहनों के चालान नहीं करेंगे और

पासिंग की व्यवस्था में भी आवश्यक सुविधा दी जाएगी।

सरकार इन वाहनों की आयु 15 साल करना चाहती है, लेकिन मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर आयु सीमा नहीं बढ़ा सकती। मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और केंद्र के निर्णय के बाद आगे की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र से मिले पत्र और अब तक किए गए पत्राचार को सदन में रखा जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही सूचनाओं के आधार पर इस मामले को नहीं

जयराम ने पूछा-प्रदेश ने क्यों नहीं की व्यवस्था

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया। केंद्र सरकार ने टैक्सी वाहनों के लिए 15 साल की व्यवस्था पहले ही कर दी थी, ऐसे में प्रदेश सरकार ने समय रहते इसे लागू क्यों नहीं किया। कहा कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन कई जगहों से 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं और वहां वाहनों में कई कमियां निकालकर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द मैनुअल फिटनेस जांच की व्यवस्था की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में टैक्सी ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस व्यवस्था का पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है।



देखा जाना चाहिए। सरकार ने केंद्र से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए भी आयु सीमा 15 साल करने का आग्रह किया है। जब तक निर्णय नहीं आता, तब तक राज्य की परिधि में ऐसे वाहनों को वैकल्पिक राहत दी जाएगी।

मुकेश ने कहा कि एआईटीपी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध व्यवस्था का लाभ ऑपरेटर उठा सकते हैं। एआईटीपी फीस कम करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। केंद्र में इस पर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्सी ऑपरेटरों के प्रति संवेदनशील है और जल्द समाधान चाहती है। उप

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

निजी क्षेत्र के दो स्टेशन काम करना शुरू कर चुके हैं। पांच और स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों में वाहनों की फिटनेस की तकनीकी आधार पर जांच होगी। उन्होंने कहा कि जब तक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैनुअल फिटनेस जांच की व्यवस्था जारी रखने के लिए केंद्र से आग्रह किया गया है। केंद्र से पत्र भी आया है और इस पर विचार-विमर्श चल रहा है।

मुख्यमंत्री धन कुबेर, इनके पास लगाओ प्रार्थना पत्र

शिमला। प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से विधायक किशोरी लाल की ओर से जब कूहल निर्माण के लिए बजट देने की मांग उठाई तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धन कुबेर हैं। इनके पास प्रार्थनापत्र लगाओ। बजट जारी हो जाएगा तो विभाग काम कर देगा। अगर विधायक जुगाड़ ही चाहते हैं तो जल शक्ति विभागों के अफसरों से कह दिया जाएगा कि आपके साथ बैठक कर लें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी एक सवाल के सवाल में विधायक मोहन लाल ब्रावटा को मुख्यमंत्री से बजट मांगने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट भाषण में विशेष प्रावधान किया है कि जिन निर्माण कार्यों का 80 फीसदी पूरा हो चुका है, उनके शेष कार्य के लिए बजट की कमी नहीं रखी जाएगी। ब्यूरो

■ **भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल**
प्रश्नकाल के दौरान कई भाजपा विधायक अनुपस्थित रहे। जबकि अपने सवालों से पहले या बाद में वे सीटों में बैठे रहे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष को संबोधित करते पूछा कि अनुपस्थिति क्यों है।